

पंचशील

प्रलेखों से सार उद्धरण

१९५४-५७

इन्द्र विद्यावाचस्पति
च. इ. को. व. ज. या. नगर
दिल्ली द्वारा
सूचना न. १०१ प्रतिकास्य को
भेद

A
5
पंशी-पं

५
२

४.५

२ ११

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तकालय



विषय संख्या

पुस्तक संख्या

प्राप्त पञ्जिका संख्या ३२,०६३

पुस्तक पर मालिकाना अधिकार की निशानियाँ
लगायी गयी हैं। पुस्तक १५ दिन से अधिक
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

भारतपूर्व उपकुलपति द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी
विश्वविद्यालय को दी गयी पुस्तकें संप्रति भेंट

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
किसी पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

स्वागत समारोह ११-४-११

२

हम सभी के साथ मैत्री, भाईचारे तथा सभी प्रकार के भावों तथा विचारों के आदान-प्रदान का स्वागत करते हैं। किन्तु हम अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार अपने हाथ में ही सुरक्षित रखेंगे। पंचशील का यही सार है।

—जवाहरलाल नेहरू

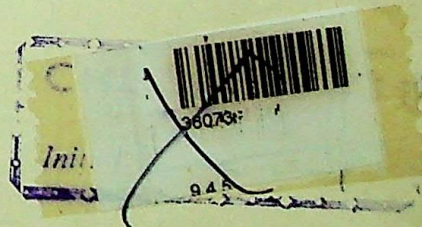
३० नवम्बर, १९५५

हम विद्यावाचस्पति

च-प्रदीप, जवाहर नगर

दिल्ली द्वारा

मुख्य कार्यालय पुस्तकालय को
३६



M61LS

R 9.5,PAN-P



38073

● ग्रन्थ प्रमाण पुष्टि: ●	
पुस्तक नं.	२०४
भाग नं.	२
लिपि:	२२०६३
गुरुकुल, देहरादून	

आमुख

पंचशील के नाम से प्रसिद्ध शांतिमय सहअस्तित्व के पांच सिद्धान्तों की नींव सर्वप्रथम २९ अप्रैल, १९५४ को तिब्बत के बारे में भारत और चीन के बीच हुए समझौते में रखी गई थी। उस समय से अब तक की तीन वर्ष की अवधि में संसार के कई देशों ने इनके फैलाने में योग दिया है और अनेक देश इनका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने व्यवहार के आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार कर चुके हैं।

इस पुस्तिका में, जो मूल अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद है, पंचशील के बारे में भिन्न-भिन्न राज्यों के मुखियाओं, प्रधान मंत्रियों अथवा विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न प्रलेखों से सार-उद्धरण एकत्रित करके उन्हें एक सुविधापूर्ण रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

हमें आशा है कि इस सचिवालय द्वारा इस विषय पर प्रकाशित अन्य पुस्तिकाओं के साथ-साथ सदस्यों के लिये यह पुस्तिका भी उपयोगी तथा ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगी।

नई दिल्ली,
१० मई, १९५७

महेश्वर नाथ कौल,
सचिव।

विषय-सूची

आमुख	...	...	...	...	...	...	...	पृष्ठ (क)
१. तिब्बत सम्बन्धी भारत-चीन समझौता (अप्रैल, १९५४)	...	...	...	...	...	...	...	१-२
२. चाऊ-नेहरू संयुक्त वक्तव्य (जून, १९५४)	...	...	...	...	...	...	...	३-४
३. चाऊ-ऊ नू संयुक्त वक्तव्य (जून, १९५४)	...	...	...	...	...	...	...	५-६
४. भारत-वियत नाम संयुक्त वक्तव्य (अक्तूबर, १९५४)	...	...	...	...	...	...	...	७-८
५. टीटो-नेहरू संयुक्त वक्तव्य (दिसम्बर, १९५४)	...	...	...	...	...	...	...	९-१०
६. टीटो-ऊ नू संयुक्त वक्तव्य (जनवरी, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	११-१२
७. भारत-कम्बोडिया संयुक्त वक्तव्य (मार्च, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	१३-१४
८. भारत तथा वियत नाम के विदेश मंत्रियों का वक्तव्य (अप्रैल, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	१५-१६
९. एशियाई सम्मेलन का संकल्प (अप्रैल, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	१७-१८
१०. एशियाई-अफ्रीका सम्मेलन (अप्रैल, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	१९-२१
११. चीनी-इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य (अप्रैल, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	२३-२४
१२. टीटो-बुल्गानिन संयुक्त वक्तव्य (जून, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	२५-२६
१३. बुल्गानिन-नेहरू संयुक्त वक्तव्य (जून, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	२७-२८
१४. भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य (जून, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	३१-३२
१५. टीटो-नेहरू दूसरा संयुक्त वक्तव्य (जुलाई, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	३३-३४
१६. भारत-लाओस संयुक्त वक्तव्य (सितम्बर, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	३५-३६
१७. भारत-सऊदी अरब संयुक्त वक्तव्य (दिसम्बर, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	३७-३८
१८. भारत-सोवियत दूसरा संयुक्त वक्तव्य (दिसम्बर, १९५५)	...	...	...	...	...	...	...	३९-४०
१९. टीटो-नासिर-नेहरू संयुक्त वक्तव्य (जुलाई, १९५६)	...	...	...	...	...	...	...	४१-४२
२०. भारत-सऊदी अरब दूसरा संयुक्त वक्तव्य (सितम्बर, १९५६)	...	...	...	...	...	...	...	४३-४४
२१. चीन-नेपाल संयुक्त वक्तव्य (अक्तूबर, १९५६)	...	...	...	...	...	...	...	४५-४६
२२. भारत-इथोपिया संयुक्त वक्तव्य (नवम्बर, १९५६)	...	...	...	...	...	...	...	४७-४८
२३. भारत-सीरिया संयुक्त वक्तव्य (जनवरी, १९५७)	...	...	...	...	...	...	...	४९-५०
२४. भारत-पोलैंड दूसरा संयुक्त वक्तव्य (मार्च, १९५७)	...	...	...	...	...	...	...	५१-५२
२५. भारत-चिली संयुक्त वक्तव्य (अप्रैल, १९५७)	...	...	...	...	...	...	...	५३-५४
२६. भारत-लंका संयुक्त वक्तव्य (मई, १९५७)	...	...	...	...	...	...	...	५५-५६

(ख)

अध्याय १

तिब्बत सम्बन्धी भारत-चीन समझौता

[अप्रैल, १९५४]

इन्द्र विद्यावाचस्पति
ज. प्रसोक, जवाहर नगर
दिल्ली द्वारा
पुरवा नाली पुस्तकालय को
भेंट

इस समझौते ने दो महान् देशों के बीच मैत्री की पुष्टि की है। एशिया तथा विश्व में शांति बनाये रखने के लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। इस समझौते में ऐसे सिद्धान्तों की बुनियाद रखी गई है, जिन पर कि बड़े व्यापक पैमाने पर अमल किया जा सकता है, और कई देश इनको स्वीकार भी कर चुके हैं। ये पांच सिद्धान्त जिनको 'पंचशील' के नाम से भी पुकारा जाता है, ... मैं आपके निकट इनकी प्रशंसा करता हूँ और सच्चे दिल से विश्वास करता हूँ कि ये उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार बनते जायेंगे तथा सारे संसार में शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखेंगे।

—राजेन्द्र प्रसाद

[२१ फरवरी, १९५५]

भारत और चीन के बीच व्यापार तथा समागम के समझौते के समय जारी की गई विज्ञप्ति का सार-उद्धरण

[२६ अप्रैल, १९५४]

दोनों पक्षों ने एक दूसरे के देश की सीमाओं का उल्लंघन न करने और उनकी प्रादेशिक अखंडता और प्रभु-सत्ता का समादर करने; एक दूसरे पर आक्रमण न करने; एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, और समता, परस्पर सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर एक दूसरे से बातचीत करने की सहमति प्रकट की ।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर दोनों देशों ने चीन के तिब्बत प्रदेश के बारे में भारत तथा चीन के बीच वर्तमान समस्याओं पर भली भांति चर्चा की तथा २६ अप्रैल, १९५४ को निम्नलिखित समझौता किया ।

* * * * *

भारत के गणतन्त्र की सरकार तथा चीन के जनवादी गणतन्त्र की केन्द्रीय लोक सरकार :

चीन के तिब्बत प्रदेश तथा भारत के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक समागम को प्रोत्साहन देने की इच्छा से तथा भारत और चीन के लोगों को तीर्थों तथा यात्रा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने की इच्छा से निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर वर्तमान करार करने का संकल्प करती है :

- (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता का परस्पर समादर;
- (२) परस्पर अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समता तथा परस्पर सहयोग; और
- (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

अध्याय २

चाऊ-नेहरू संयुक्त वक्तव्य

[जून, १९५४]

भारत और चीन के, जिन्होंने कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों को सबसे पहले प्रचलित किया है, बीच मैत्री तथा सहयोग का विश्व शांति के संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्द्धन में एक विशेष महत्व है।

—चाऊ-एन-लाई

[२८ नवम्बर, १९५४]

भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२८ जून, १९५४]

हाल ही में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें उन्होंने कतिपय ऐसे सिद्धान्तों की बुनियाद रखी है, जिनके आधार पर इन दोनों देशों के सम्बन्ध संचालित किये जायेंगे । वे सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

- (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर समादर;
- (२) परस्पर अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समता तथा परस्पर सहयोग; और
- (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने इन सिद्धान्तों की पुष्टि की तथा यह इच्छा प्रकट की कि एशिया तथा संसार के अन्य भागों के देशों के साथ भी इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित किये जायें । उन्होंने यह कहा कि अगर इन सिद्धान्तों को केवल दो देशों के बीच में ही व्यवहार में न लाकर इनका सामान्य रूप से सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रयोग किया जाये तो इन से शांति तथा सुरक्षा की नींव भी सुदृढ़ हो सकती है और आजकल जो भय तथा आशंकाओं का वातावरण बना हुआ है उसके स्थान पर राष्ट्रों में परस्पर विश्वास की भावना बढ़ सकती है ।

प्रधान मंत्रियों ने स्वीकार किया कि एशिया तथा विश्व के विभिन्न भागों में- भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक तथा राजनीतिक पद्धतियां हैं । किन्तु उन्होंने कहा कि यदि उपर्युक्त सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया जाये और उन पर अमल किया जाने लगे और अगर कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, तो फिर इस प्रकार के भेद-भाव विश्व-शांति के मार्ग में आड़े नहीं आ सकते और न उनसे किसी प्रकार का संघर्ष ही उत्पन्न हो सकता है । प्रत्येक देश की प्रादेशिक अखण्डता तथा संप्रभुता के अश्वस्त हो-जाने से तथा आक्रमण की आशंका के दूर हो जाने से भिन्न-भिन्न देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बना रहेगा और उन में परस्पर मैत्री बढ़ने लगेगी । इससे आज की दुनियां का तनाव कम हो जायेगा और विश्व में शांति का वातावरण पैदा करने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने विशेष रूप से यह आशा प्रकट की है कि हिन्द-चीन की समस्याओं को इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हल किया जाये, क्योंकि वहां पर राजनीतिक दृष्टि से एक ऐसे स्वतन्त्र, प्रजातांत्रिक संगठित तथा स्वाधीन राज्य बनाने की आवश्यकता है जिस पर किसी प्रकार के विदेशी आक्रमण का भय न रहे और जिस में कोई भी विदेशी शक्ति हस्तक्षेप न कर सके । ऐसा होने पर इन देशों में आत्म-विश्वास की भावना जागृत होगी और पड़ोसी देशों के साथ भी इनका मैत्री सम्बन्ध बढ़ने लगेगा । इस प्रकार ऊपर कहे गये सिद्धान्तों को अपना लेने से विश्व में परिस्थितियों के अनुसार शांति का क्षेत्र बढ़ाने में बड़ी सहायता मिल सकती है । इनसे सर्वत्र युद्ध की सम्भावनायें कम की जा सकती हैं और विश्व में शांति को समृद्ध किया जा सकता है ।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने भारत और चीन की मित्रता में पूरा विश्वास प्रकट किया और कहा कि इस से परस्पर दोनों देशों तथा एशिया के अन्य देशों में भी शांतिपूर्ण ढंग से विकास करने में तथा विश्व में शांति की स्थापना में बड़ी सहायता मिलेगी ।

अध्याय ३

चाऊ-ऊ नू संयुक्त वक्तव्य

[जून, १९५४]

एशिया के सभी देश शांति चाहते हैं। आज एशिया की शांति को बाहर से भय है, परन्तु आज का एशिया पहले वाला एशिया नहीं रहा है। वह युग अब सदा के लिये बीत चुका है जब कि बाहर की शक्तियाँ अपनी इच्छानुसार एशिया के भाग्य का निर्णय कर सकती थीं।

—चाऊ-एन-लाई

[२६ जून, १९५४]

बर्मा और चीन के प्रधान मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२६ जून, १९५४]

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि वे संसार में विशेषतः दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति बनाये रखने के लिये अनवरत प्रयत्न करेंगे और उन्होंने आशा व्यक्त की कि जेनेवा में हिन्द-चीन में शांति की स्थापना की जो बात चल रही है, वह सन्तोषपूर्वक ढंग से सफल होगी ।

भारत और चीन के सम्बन्धों के मार्ग-दर्शन के जो सिद्धान्त स्थिर हुए थे, अर्थात्

- (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर समादर;
- (२) परस्पर अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समता तथा परस्पर सहयोग; और
- (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने उनसे सहमति प्रकट की और कहा कि चीन और बर्मा के बीच भी इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित किये जायें । उन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी देश इन सिद्धान्तों का पालन करने लगे तो भिन्न-भिन्न सामाजिक पद्धतियों वाले देशों में भी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बना रह सकता है और युद्ध के भय, धमकियों और एक दूसरे के देश में हस्तक्षेप करने की आशंकाओं के स्थान पर संसार के देशों में सुरक्षा तथा परस्पर विश्वास की भावना बढ़ सकती है ।

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने इस बात में आस्था प्रकट की कि प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को किसी भी दूसरे राष्ट्र के हस्तक्षेप के लिये अपनी राज्य पद्धति तथा जीवन का तरीका चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि क्रांतियों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिये और साथ ही किसी भी राष्ट्र के लोगों द्वारा व्यक्त सामान्य इच्छा के रूप में किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं सहन किया जाना चाहिये ।

अध्याय ४

भारत-वियत नाम संयुक्त वक्तव्य

[अक्तूबर, १९५४]

यदि विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सम्बन्धों में इन सिद्धांतों को अपना लें तो सम्भवतः आज के संसार के अनेक संकटों का अन्त हो सकता है ।

—जवाहरलाल नेहरू
[१५ मई १९५४]

वियत नाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री हो-ची-मिन्ह तथा भारत के
प्रधान मंत्री के संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[अक्तूबर १७, १९५४]

राष्ट्रपति हो-ची-मिन्ह.....सभी शेष समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से तथा परस्पर सहयोग से हल करना चाहते थे, ताकि हिन्द-चीन के सभी देश स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकें तथा वे किसी भी बाह्य हस्तक्षेप के बिना समृद्धि कर सकें। उन्हें भारत तथा चीन के प्रधान मन्त्रियों द्वारा प्रतिपादित पांच सिद्धान्तों में पूर्ण विश्वास था और वह वियत नाम के लाओस तथा कम्बोडिया के साथ परस्पर सम्बन्धों में तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्धों में भी उन सिद्धान्तों को लागू करना चाहते थे।

भारत के प्रधान मंत्री उनसे इस बात पर पूर्ण सहमत थे कि इन सिद्धान्तों पर अमल करने से विभिन्न देशों के बीच जो कठिनाइयां तथा परस्पर आशंकायें हैं, वे दूर हो जायेंगी तथा इनसे उन देशों में मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने तथा शांतिपूर्ण सहयोग बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलेगी।

अध्याय ५

टीटो-नेहरू संयुक्त वक्तव्य

[दिसम्बर, १९५४]

आज की स्थिति में सह-अस्तित्व की नीति के सिद्धान्त सारे संसार में द्रुत गति से घर करते जा रहे हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के रूप में निरन्तर व्यक्त हो रहे हैं ।

—जे० बी० टीटो
[१ जुलाई, १९५५]

संसद् के सम्मुख रखे गये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री के
संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२३ दिसम्बर, १९५४]

यूगोस्लाविया और भारत इस बात को भली भाँति समझते हैं कि उनकी अनथक परिश्रमों से प्राप्त की हुई प्रिय स्वतन्त्रता केवल शांति द्वारा ही समेकित रह सकती है और शांति के लिये यत्नशील रहने पर ही उनके देशवासियों को आत्म विकास, आर्थिक प्रगति तथा समृद्धि एवं सामाजिक उन्नति व स्थिरता का अवसर प्राप्त हो सकता है ।

प्रेसीडेंट और प्रधान मंत्री परस्पर विचार विमर्श के पश्चात् इस बात की इच्छा प्रकट करते हैं कि उनके देशों तथा सरकारों के सम्बन्ध एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डता की स्वीकृति, एक दूसरे पर अनाक्रमण, समता, परस्पर समादर तथा एक दूसरे के अथवा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और परस्पर तथा संसार में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये वातावरण तैयार करने के सिद्धान्तों पर आधारित हों तथा आगे भी बने रहें । वे चाहते हैं कि यही मूलभूत धारणा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मार्ग-दर्शन करे तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की नीति तथा कार्य में इन तत्वों को प्राथमिक स्थान दिया जाये ।

इसका यह तात्पर्य है कि इन दो देशों की नीति तथा विश्व शांति के लिये प्रयासों को बल अथवा शस्त्रास्त्रों के संग्रह पर आधारित नहीं किया जा सकता है । अस्त्रों के संग्रह के बल पर संघर्षों के द्वारे में न तो कोई बातचीत चलाई जा सकती है और न उनका समाधान ही किया जा सकता है । इसलिये प्रेसीडेंट तथा प्रधान मंत्री गुटों में न आने वाले देशों के बारे में संसार के कुछ भागों में 'फैल रही तीसरे गुट' अथवा 'तीसरी शक्ति' की भ्रामक धारणा का खण्डन करते हैं । यह बात उनके सिद्धान्तों के विरुद्ध है, क्योंकि इस प्रकार का 'गुट' उन्हें एक प्रकार के गठबन्धन में ग्रस्त कर देगा जिसे वे सदा अवांछनीय मानते आये हैं ।

प्रेसीडेंट तथा प्रधान मंत्री को पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जिन सिद्धान्तों पर आपसी सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया है उनको अधिक विस्तृत रूप में भी अपनाया जा सकता है । यदि इनको स्वीकार कर लिया जाये तो ये संसार की तनातनी को दूर करने में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं तथा कई लम्बमान झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं । इनसे शांति का क्षेत्र बढ़ेगा और युद्ध की भयानक सम्भावनायें कम हो जायेंगी । इन से एक दूसरे के प्रति अधिक विश्वास बढ़ेगा तथा विश्व में सहयोग के लिये नये अवसर उत्पन्न हो जायेंगे ।

प्रेसीडेंट तथा प्रधान मंत्री सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करते हैं कि संसार के लोगों की प्रगति करने की आशाएँ तथा संसार की सम्यक्ताओं के अस्तित्व का प्रश्न इस बात को आवश्यक बना देता है कि हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों को स्वीकार करें । हम इसे केवल एक विकल्प के रूप में नहीं प्रत्युत एक अनिवार्य कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ।

अध्याय ६

टीटो-ऊ नू संयुक्त वक्तव्य

[जनवरी, १९५५]

यह बड़ा उत्साहवर्द्धक है कि इन सिद्धान्तों को
निरन्तर अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है।
वास्तव में समस्त मानव-समाज का कल्याण ही
शांति की परिभाषा है।

—जे० बी० टोटो
[१ जुलाई, १९५५]

यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति मार्शल जोसिप बरोज टीटो
तथा बर्मा संघ के प्रधान मंत्री ऊ नू के संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[१७ जनवरी, १९५५]

सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में यूगोस्लाविया और बर्मा ने अभी तक सभी मुख्य समस्याओं के बारे में तत्त्वतः एक ही जैसा खैया अपनाया है और आज भी इन समस्याओं के बारे में उनके विचार एक समान हैं ।

यूगोस्लाविया और बर्मा के नेताओं को दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में केवल सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर ही शांति कायम रह सकती है । इन सिद्धान्तों को लागू करने के लिये तथा संसार की सभी समस्याओं का हल करने के लिये, खास तौर पर ऐसी समस्याएँ जिन के कारण कि संसार में बड़ी तनातनी फैली हुई है, संसार के सभी देशों को अपने-अपने देशों की राजनीतिक तथा सामाजिक पद्धतियों के अन्तर्गत् से ऊपर उठकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की भावना से शांतिमय सहयोग द्वारा सतत तथा सक्रिय प्रयत्न करने होंगे । परस्पर प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता तथा प्रभु-सत्ता, अनाक्रमण, समता तथा दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों को इस सहयोग का आधार बनाया जा सकता है । सह-अस्तित्व की नीति को स्थायी रूप से अपना लेने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी होने की सम्भावना हो जायेगी और इस से स्थिर तथा स्थायी शांति के लिये मार्ग तैयार हो जायेगा । इसलिये यूगोस्लाविया और बर्मा की सरकारें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखने के क्षेत्र में सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों पर अमल करने के लिये प्रयत्न करेंगी ।

अध्याय ७

भारत-कम्बोडिया संयुक्त वक्तव्य

[मार्च, १९५५]

मेरे देशवासियों की भारत क साथ निश्चित आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने की जो भावना है, भारतवासियों में भी वही भावना देख कर मुझे बड़ा [हर्ष हुआ है। हम सदा पड़ोसी राष्ट्र रहे हैं और आज मुझे इन निष्कर्षों को अपने लोगों तक पहुंचाने में बड़ा आनन्द प्राप्त हो रहा है।

—नरोत्तम सिंहानूक

[२४ मार्च, १९५५]

तत्रभवान् राजकुमार नरोत्तम सिंहानूक वसन और कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री तथा भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा नई दिल्ली में दिये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[१८ मार्च, १९५५]

कम्बोडिया के शिष्टमंडल के नेता ने विश्व की समस्याओं के बारे में भारत की सामान्य नीति तथा विश्व में शांति बनाये रखने के लिये भारत की उत्कट-इच्छा की भूरि-भूरि प्रशंसा की। कम्बोडिया की शाही सरकार के शिष्टमंडल तथा भारत के प्रधान मन्त्री ने इस बात से सहमति प्रकट की कि विश्व में शांति की स्थापना की तथा विभिन्न देशों में मित्रता बनाये रखने की यही सर्वोत्तम गारंटी है कि सब देश एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डता एवं परस्पर अनाक्रमण और समता को स्वीकार करें व एक दूसरे तथा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये वातावरण उत्पन्न करने के इन सिद्धान्तों को अपना लें।

अध्याय ८

भारत तथा वियत-नाम के विदेश मन्त्रियों का वक्तव्य

[अप्रैल, १९५५]

विश्व में शांति की स्थापना की तथा विभिन्न देशों में मित्रता बनाये रखने की यही सर्वोत्तम गारंटी है कि सब देश एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डता एवं परस्पर अनाक्रमण और समता को स्वीकार करें व एक दूसरे तथा अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये वातावरण उत्पन्न करने के इन सिद्धान्तों को अपना लें ।

—नेहरू-फान वान डोंग संयुक्त वक्तव्य से

[१० अप्रैल, १९५५]

प्रधान मन्त्री नेहरू और वियत-नाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के उपप्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री
श्री फान वान डोंग के बीच वार्तालाप पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति का सार-उद्धरण

[१० अप्रैल, १९५५]

दोनों नेताओं ने अपने इस विश्वास की पुष्टि की कि वियत-नाम, कम्बोडिया और लाओस के बीच जनेवा समझौते तथा पंचशील के सिद्धान्तों के अनुसार अच्छे पड़ोसी देशों के से सम्बन्धों तथा परस्पर समादर तथा सहनशीलता की भावना से हिन्द-चीन में राजनीतिक हल ढूँढने में बड़ी सहायता मिलेगी और इससे दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति की भावना को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा ।

वियत-नाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के उपप्रधान मन्त्री तथा भारत के प्रधान मन्त्री ने इस बात से सहमति प्रकट की कि विश्व में शांति स्थापना की तथा विभिन्न देशों में मित्रता बनाये रखने की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि सब देश एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डता एवं परस्पर अनाक्रमण, समता तथा एक दूसरे तथा अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये वातावरण उत्पन्न करने के सिद्धान्तों को अपना लें ।

अध्याय ६

एशियाई सम्मेलन का संकल्प

[१० अप्रैल, १९५५]

भिन्न-भिन्न पद्धतियों को अपनाने वाले देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त संसार के लोगों में न केवल लोकप्रिय हो गया है और लाखों शांतिप्रिय लोगों के लिये उनका एक सामान्य विश्वास बन चुका है प्रत्युत वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक वास्तविक तथ्य का रूप भी धारण कर चुका है ।

—चाऊ-एन-लाई

[४ अक्तूबर, १९५५]

नई दिल्ली में हुये एशियाई सम्मेलन द्वारा पास किये गये संकल्प का मूल पाठ

[१० अप्रैल, १९५५]

एशियाई देशों का यह सम्मेलन भारत तथा चीन के प्रधान मन्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तथा कई अन्य देशों द्वारा संपुष्ट निम्नलिखित पांच सिद्धान्तों की पूर्णरूपेण पुष्टि करता है; (क) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर समादर; (ख) अनाक्रमण; (ग) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना; (घ) समता तथा परस्पर सहयोग; (ङ) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व ।

सम्मेलन को पूर्ण विश्वास है कि ये सिद्धान्त राष्ट्रों में परस्पर समबोध तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये एक निश्चित आधार स्तम्भ बन सकते हैं ।

यह सम्मेलन भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के इस कथन से पूर्णता सहमत है कि ये सिद्धान्त एशिया की ओर से विश्व के लिये एक चुनौती हैं और प्रत्येक देश को इनका सीधा उत्तर देना होगा ।

हम एशिया तथा विश्व के सभी देशों से अपील करते हैं कि वे इन सिद्धान्तों का पूर्ण समर्थन करें तथा इनके तात्पर्यों का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्वचन तथा आदर करें ।

हम एशिया तथा विश्व की सभी सरकारों को आमंत्रित करते हैं कि वे सभी देशों के साथ अपने सम्बन्धों में इन सिद्धान्तों को आधार बनायें ।

अध्याय १०

एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन

[अप्रैल, १९५५]

बांडुंग घोषणा में हमें ये पांच सिद्धान्त अपने पूर्ण रूप में और ऐसी व्याख्याओं के साथ समृद्ध रूप में देखने को मिलते हैं जो इन्हें और सुदृढ़ कर देती हैं। हमें इस बात का हर्ष है कि विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधि सम्मेलन में इन सिद्धान्तों को अपने व्यवहार तथा विश्व के सम्बन्धों में शांति तथा सहयोग की प्राप्ति के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है।

—जवाहरलाल नेहरू

[३० अप्रैल, १९५५]

बांडुंग में हुए एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति का

सार-उद्धरण

[१८-२४ अप्रैल, १९५५]

विश्व शांति तथा सहयोग की वृद्धि के लिये घोषणा

एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन ने विश्व शांति तथा सहयोग के प्रश्न पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। यह सम्मेलन वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनावों की स्थिति पर, जिसमें आणविक विश्व युद्ध का खतरा निहित है, बड़ी चिन्ता प्रकट करता है। शांति की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या से सम्बद्ध है। अतः सभी देशों को शांति की स्थापना के लिये परस्पर सहयोग करना चाहिये और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन्हें प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अधीन अस्त्रों की कमी करने तथा आणविक हथियारों को समाप्त करने के लिये सहयोग करना चाहिये। इस तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय शांति की वृद्धि हो सकती है और नाभिकीय ऊर्जा का केवल शांतिमय कार्यों के लिये प्रयोग सम्भव हो सकता है। इससे विशेषतः एशिया तथा अफ्रीका की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। आज एशिया तथा अफ्रीका को सामाजिक प्रगति, अच्छे जीवनस्तर तथा अधिक स्वतन्त्रता की विशेष आवश्यकता है। स्वतन्त्रता और शांति अन्योन्याश्रित है। सभी राष्ट्रों को आत्म निर्णय का अधिकार होना चाहिये तथा जो देश अब भी परतंत्र हैं, उन्हें बिना किसी विलम्ब के फौरन स्वतन्त्रता प्रदान की जानी चाहिये। सभी राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के अनुसार अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक पद्धति तथा अपने रहने-सहने के ढंग के चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

राष्ट्रों को अविश्वास तथा भय से रहित होकर तथा परस्पर विश्वास और सौहार्द की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का बतवि करना चाहिये और एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसियों की भांति शांतिपूर्वक रहना चाहिये तथा निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर परस्पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना चाहिये :

- (१) मूलभूत मानव अधिकारों तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के प्रति समादर।
- (२) सभी राष्ट्रों की प्रभु सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता का समादर।
- (३) सभी बड़े तथा छोटे राष्ट्रों की समता को स्वीकार करना।
- (४) दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से विलग रहना अथवा उनमें हस्तक्षेप न करना।
- (५) संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुकूल प्रत्येक राष्ट्र के अकेले अथवा सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करने के अधिकार का समादर।
- (६) (क) किसी बड़ी शक्ति के विशेष हितों की पूर्ति के लिये सामूहिक रक्षा के प्रबन्ध करने से विलग रहना।
- (ख) किसी भी दूसरे देश पर दबाव डालने से विलग रहना।

- (७) किसी भी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा प्रादेशिक अखण्डता के विरुद्ध आक्रमण करने अथवा आक्रमण करने की धमकियाँ देने अथवा बल प्रयोग करने से दूर रहना ।
- (८) सभी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र अनुकूल शांतिमय ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करना जिसमें वार्तालाप, संराधन, मध्यस्थ, निर्णय अथवा न्यायिक समझौता अथवा दोनों पक्षों की रजामन्दी से चुना गया कोई भी अन्य शांतिपूर्ण तरीका सम्मिलित है ।
- (९) पारस्परिक हितों की वृद्धि के लिये सहयोग करना ।
- (१०) न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का समादर ।

एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन ने अपने इस विश्वास की घोषणा की कि इन सिद्धान्तों के अनुसार मैत्रीपूर्ण सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाये रखने तथा आगे बढ़ाने में बड़ा प्रभावी योग मिलेगा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग से सभी की समान समृद्धि तथा कल्याण में बड़ी सहायता मिलेगी ।



अध्याय ११

चीन-इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य

[अप्रैल, १९५५]

इंडोनेशिया की गृह तथा बाह्य राजनीति
की विचारधारा को समझने के लिये पंच सील
(पंचशील) के दर्शन को समझना जरूरी होगा ।

—ए० शस्त्रमिजोयो

[२३ सितम्बर, १९५४]

चीन और इंडोनेशिया के प्रधान मन्त्रियों के संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२८ अप्रैल, १९५५]

१. दोनों प्रधान मन्त्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन द्वारा सुनिश्चित सामान्य आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उस सम्मेलन द्वारा विश्व शांति तथा सहयोग को बढ़ाने के लिये अंगीकृत घोषणा को पूरा करने के लिये पूर्ण प्रयत्न करेंगे ।
२. दोनों प्रधान मन्त्रियों को सन्तोष है कि चीन और इंडोनेशिया परस्पर प्रभु-सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता के समादर, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, समता तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के सिद्धान्तों के आधार पर एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसियों की भांति रह रहे हैं । उन्हें दृढ़ विश्वास है कि इन सिद्धान्तों के आधार पर दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ेंगे ।

*

*

*

४. दोनों प्रधान मन्त्री घोषणा करते हैं कि किसी भी देश के लोगों को अपनी प्रभु-सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करने का परम अधिकार है और वह उनसे छीना नहीं जा सकता है । वे दोनों देशों के परस्पर प्रभु-सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखने के प्रयत्नों के लिये सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा उनका पूर्ण समर्थन करते हैं ।
५. दोनों प्रधान मन्त्री दोनों देशों के बीच परस्पर समादर समता तथा सहयोग के आधार पर आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर सहायता तथा सहयोग के बढ़ने की पूर्ण आशा करते हैं । उनका विचार है कि दोनों देशों के बीच इस प्रकार की परस्पर सहायता तथा सहयोग से उन दोनों देशों तथा विश्व में शांति के संवर्द्धन में बड़ी सहायता मिलेगी ।

अध्याय १२

टीटो-बुल्गानिन संयुक्त वक्तव्य

[जून, १९५५]

यूगोस्लाविया और सोवियत संघ के बीच
सर्वांगीण सहयोग दोनों देशों, अन्य राष्ट्रों तथा,
विश्व शांति एवं समाजवाद के पूर्ण हित में है ।

—एन० झुश्चेव

[३ जून, १९५५]

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा सोवियत संघ के प्रधान मन्त्री के संयुक्त वक्तव्य का

सार-उद्धरण

[२ जून, १९५५]

दोनों देशों ने अपनी वार्तालाप के दौरान में सामने आने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिये तथा राष्ट्रों में परस्पर विश्वास तथा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर बातचीत शुरू की थी :

- (१) शांति के आधार पर ही विश्व की सामूहिक सुरक्षा बनी रह सकती है ।
- (२) राज्यों द्वारा आपसी सम्बन्धों तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्धों में एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा समता समादर ।
- (३) सैद्धांतिक मतभेदों अथवा सामाजिक व्यवस्था के भेदों पर बिना ध्यान दिये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मान्यता देना और उसका संवर्द्धन, जिस के लिये विश्व के सभी देशों का सामान्य रूप से समग्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में तथा विशेष रूप से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग एक प्राथमिक आवश्यकता है ।
- (४) किसी भी कारण से एक दूसरे के आर्थिक, राजनीतिक अथवा सैद्धांतिक स्वरूप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और परस्पर समादर के सिद्धान्तों का परिपालन क्योंकि भिन्न-भिन्न सामाजिक पद्धतियों तथा समाजवादी विकास के भिन्न-भिन्न रूपों वाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रश्न प्रत्येक देश के लिये सर्वथा निजी प्रश्न है ।
- (५) पारस्परिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग की वृद्धि करना तथा आर्थिक क्षेत्र में उन सब बातों को दूर करना जिन के कारण वस्तुओं के विनिमय में तथा राष्ट्रों की आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के तत्वों के सम्बन्ध में बाधा पहुँचती है ।
- (६) संयुक्त राष्ट्र के उपयुक्त निकायों द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों के अनुकूल अन्य उपायों द्वारा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या कम विकासशील क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिये और विश्व की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये एक दूसरे की सहायता करना ;
- (७) सभी प्रकार के आक्रमणों तथा दूसरे देशों को राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाने के सभी प्रयत्नों की भर्त्सना करना ।

अध्याय १३

बुल्गानिन-नेहरू संयुक्त वक्तव्य

[जून, १९५५]

जब एक देश दूसरे देश पर प्रभुत्व जमाने अथवा उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है तभी सब मुसीबतें पैदा होती हैं। यदि संसार के सभी देश सन्चाई पूर्वक पंचशील को अपना लें, तो सभी और शांति का साम्राज्य फैल सकता है और सहयोग बढ़ सकता है..... भारत तथा सोवियत संघ की राजनीतिक पद्धतियां भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु फिर भी हम मित्र देश हैं और कई प्रकार से एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं; क्योंकि हम एक दूसरे की स्वतन्त्रता का समादर करते हैं और एक दूसरे की जीवन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

—जवाहरलाल नेहरू

[३० नवम्बर, १९५५]

मार्शल बुल्गानिन और श्री नेहरू के संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२३ जून, १९५५]

सौभाग्य से भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध मित्रता तथा परस्पर समवबोध की दृढ़ नींव पर आधारित हैं। दोनों प्रधान मन्त्रियों का दृढ़ संकल्प है कि ये सम्बन्ध निम्नलिखित सिद्धान्तों से अनुप्राणित होते रहेंगे और दिग्निर्देश प्राप्त करते रहेंगे :

- (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर समादर;
- (२) अनाक्रमण;
- (३) किसी भी कारण से एक दूसरे के आर्थिक, राजनैतिक अथवा सैद्धान्तिक किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समता तथा परस्पर सहयोग; और
- (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

दोनों प्रधान मन्त्रियों का यह दृढ़ विश्वास है कि ये सिद्धान्त जिन्हें हाल में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा चुका है व्यापक रूप से लागू किये जा सकते हैं तथा यदि संसार के देश एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करते समय इन पर अमल करें तो उनके मनों से एक दूसरे के प्रति भय तथा अविश्वास दूर होने की तथा विश्व में तनाव कम होने की पूरी आशा हो सकती है।

इन सिद्धान्तों को अपेक्षतया व्यापक रूप में लागू करने से शांति के क्षेत्र का विस्तार होगा, राष्ट्रों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहयोग की भावना फैलेगी। इस प्रकार शांति का वातावरण उत्पन्न हो जाने पर संसार की समस्याओं का वार्तालाप तथा समझौतों द्वारा शांतिमय ढंग से हल ढूँढे जाने की सम्भावना बढ़ जायेगी।

दोनों प्रधान मन्त्री अनुभव करते हैं कि संसार के भिन्न-भिन्न भागों में छोटे तथा अपेक्षतया कमजोर देशों में बड़ी शक्तियों की ओर से अस्पष्ट तथा अयुक्तिसंगत भय फैल रहा है। वे लोगों के मन से इस भय को सभी सम्भव तरीकों से निकाल देना आवश्यक समझते हैं। इसका सब से बढ़िया तरीका यही है कि लोग दृढ़ निष्ठा से ऊपर गिनाये गये पांच सिद्धान्तों पर डटे रहें।

दोनों प्रधान मन्त्री पिछले अप्रैल में बांडुंग में हुए एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के प्रस्तावों की सराहना करते हैं। यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक महत्व का सम्मेलन था। यह अपनी किस्म का पहला सम्मेलन था जिस में दो महाद्वीपों के भिन्न-भिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक पद्धतियों वाले राष्ट्र आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के साधनों तथा ढंगों पर विचार करने के लिये इकट्ठे हुए थे। इस सम्मेलन के बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं और वे केवल सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपितु विश्व-शांति की दृष्टि से भी बड़े उत्साहवर्धक हैं।

प्रधान मन्त्री विशेष रूप से एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन द्वारा विश्व-शांति तथा सहयोग के बारे में स्वीकृत किये गये संकल्प का स्वागत करते हैं जिसमें कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की धारणा की ही व्याख्या तथा अभिव्यक्ति की गई है।

* * * * *

प्रधान मन्त्रियों का विश्वास है कि इस वक्तव्य में प्रतिपादित पांच सिद्धान्तों के तत्वावधान में उनके दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग बढ़ सकता है। यह बात कि इन में से प्रत्येक देश अपनी-अपनी परम्परा, प्रतिभा तथा परिस्थितियों के अनुकूल भिन्न-भिन्न पद्धतियों का अनुकरण कर रहा है, उनके बीच पारस्परिक सहयोग में बाधा नहीं बननी चाहिये।

वास्तव में सच्चे सह-अस्तित्व का जिस में कि दोनों प्रधान मन्त्रियों की पूर्ण निष्ठा है यही अभिप्राय है कि भिन्न-भिन्न सामाजिक ढांचों वाले राष्ट्र भी अमन और चैन से साथ-साथ रह सकते हैं और वे सर्वसामान्य के कल्याण के लिये मिल कर काम कर सकते हैं।

अध्याय १४

भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य

[जून, १९५५]

प्रत्येक देश को अपने भविष्य के निर्माण के तरीके का निर्णय स्वयं करने का अधिकार होना चाहिये। इस बात को मान कर चीन की जनवादी गणराज्य तथा भारत ने यह निश्चय किया कि दोनों देशों के बीच “पांच सिद्धान्तों” के आधार पर सम्बन्ध स्थापित किया जाय। इसके पश्चात् बर्मा तथा यूगोस्लाविया ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और अब सोवियत संघ भी उनका समर्थन कर चुका है। बांडुंग सम्मेलन में इन सिद्धान्तों को विश्व शांति तथा सहयोग की घोषणा में दस सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार ३० से अधिक देशों ने इन को स्वीकार कर लिया है। मुझे इस में तनिक भी सन्देह नहीं है कि अगर संसार के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के इन सिद्धान्तों को अपना लें और इन पर अमल करने लगे तो आज विश्व भर में भय तथा आशंकाओं का जो घटाटोप अन्धकार छाया हुआ है वह तुरन्त दूर हो जायेगा।

—जवाहरलाल नेहरू

[२१ जून, १९५५]

भारत तथा पोलैंड के प्रधान मन्त्रियों द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का

सार-उद्धरण

[२७ जून, १९५५]

दोनों प्रधान मन्त्री उन पांच सिद्धान्तों का पूर्ण अनुमोदन करते हैं तथा उन्हें स्वीकार करते हैं जिनको कि अनेक दशों द्वारा आपसी सम्बन्धों के संचालन के लिये मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। वे पांच सिद्धान्त ये हैं : (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति समादर; (२) अनाक्रमण; (३) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किन्हीं भी कारणों से तथा आर्थिक, राजनैतिक अथवा सैद्धांतिक किसी भी रूप में हस्तक्षेप न करना; (४) समता तथा परस्पर सहयोग, और (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

अध्याय १५

टीटो-नेहरू दूसरा संयुक्त वक्तव्य

[जुलाई, १९५५]

विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं न उन सिद्धान्तों की उपयुक्तता की पुष्टी कर दी है जिनका कि हमारे दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और जिनके आधार पर हमने अपने आपसी सम्बन्धों को स्थापित किया है। सक्रिय सह-अस्तित्व की नीति के प्रति दोनों देशों की लगन की झलक उनकी सरकारों के महत्वपूर्ण कार्यों में स्पष्ट दिखाई देती है।

—जे० बी० टीटो

[१ जुलाई, १९५५]

मार्शल टीटो और श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रियोनी में दिये गये वक्तव्य का

सार-उद्धरण

[६ जुलाई, १९५५]

दोनों राजनीतिज्ञों ने जिन समस्याओं पर विचार-विनिमय किया उन पर उनके विचारों में बड़ी समानता थी । यूगोस्लाविया और भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपने कार्य के दौरान में अपने-अपने ढंग से एक ही जैसे विचारों तथा सिद्धान्तों का विकास किया है । इस से यह प्रकट होता है कि यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत गणराज्य के प्रधान मन्त्री द्वारा दिसम्बर, १९५४ को जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में व्यक्त किये गये सिद्धान्त तथा विचार समकालीन विश्व की विचार धाराओं के विकास की सामान्य प्रवृत्तियों के द्योतक हैं ।

शांतिपूर्ण और सक्रिय सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर दोनों देशों द्वारा अपनाई गई पूर्ण स्वतन्त्रता की नीति संसार के अधिकांश देशों में निरन्तर बढ़ रहे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और परस्पर समवबोध की भावना की प्रतीक है । राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकार की भावनाओं से विकास के आड़े आने वाली प्रवृत्तियों के होते हुये भी हाल में विश्व की सामान्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को वार्तालाप तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा सुलझाने की प्रवृत्ति को काफी बल मिला है तथा इस दिशा में कुछ सफलतायें भी प्राप्त हुई हैं ।

अध्याय १६

भारत-लाओस संयुक्त वक्तव्य

[सितम्बर, १९५५]

भारत और लाओस के निवासियों का एक
सांस्कृतिक उद्गम है, उनकी एक ही जैसी
समस्याएँ तथा उनका निदान भी एक ही
जैसा है ।

—के० डी० ससोरिथ
लाओस के प्रधान मन्त्री
[१९ सितम्बर, १९५५]

लाओस के राजकुमार सवंग वतन और प्रधान मन्त्री श्री ससोरिथ तथा भारत के
प्रधान मन्त्री द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२१ सितम्बर, १९५५]

सभी नेता इस बात से भी सहमति प्रकट करते हैं कि विश्व में शांति कायम रखने के तथा विभिन्न देशों में मित्रता बनाये रखने की यही सर्वोत्तम गारंटी है कि सब देश एक दूसरे की प्रभु-सत्ता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डता एवं परस्पर अनाक्रमण समता व एक दूसरे तथा अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये वातावरण उत्पन्न करने के सिद्धान्तों को अपना लें ।

अध्याय १७

भारत-सऊदी अरब संयुक्त वक्तव्य
[दिसम्बर, १९५५]

हमें यकीन है कि ये (पांच सिद्धान्त) दोनों देशों में शांति तथा मित्रता के सम्बन्ध बढ़ायेंगे और साथ ही विश्व में शांति बनाये रखने में योग देंगे ।

—इब्न सऊद

[७ दिसम्बर, १९५५]

तत्र भवान् सऊदी अरब क शाह इब्न सऊद तथा प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
दिल्ली में जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[१२ दिसम्बर, १९५५]

तत्र भवान् शाह तथा प्रधान मन्त्री स्वीकार करते हैं कि विश्व में शांति की स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है । वे विश्वास करते हैं कि संसार को विभक्त करने वाली समस्याओं को असैनिक तथा शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाना इस समय की परम् आवश्यकता है । दोनों देश इन पांच सिद्धान्तों को पूर्णतः मानते हैं, जो इस प्रकार हैं : एक दूसरे की प्रभु-सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता के प्रति समादर, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समादर और समता का व्यवहार करना तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व । उनके विचार में केवल इन्हीं सिद्धान्तों द्वारा ही विश्व के राष्ट्रों में स्थायी रूप से शांति तथा सहयोग बना रह सकता है ।

अध्याय १८

भारत-सोवियत दूसरा संयुक्त वक्तव्य

[दिसम्बर, १९५५]

पांच सिद्धान्तों पर आधारित भारत-सोवियत सम्बन्ध इस बात की प्रबल पुष्टि करते हैं कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक पद्धतियों वाले देशों में भी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा मैत्रीपूर्ण सहयोग हो सकता है। आज इस धारणा को अधिकाधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

—एन० ए० बुल्गानिन

[२१ नवम्बर, १९५५]

भारत और सोवियत संघ के प्रधान मंत्रियों व श्री लुश्चेव द्वारा नई दिल्ली में दिये

गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[१३ दिसम्बर, १९५५]

२२ जून, १९५५, को दोनों देशों द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में पांच सिद्धान्तों पर, जिन्हें कभी-कभी पंचशील के नाम से भी पुकारा जाता है, दृढ़ता से अमल करने की इच्छा प्रकट की गई थी। इन सिद्धान्तों में इस बात का जिक्र किया गया था कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पद्धतियों वाले देश भी एक दूसरे के साथ परस्पर समादर, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करते हुए तथा समान रूप से शांति तथा मानव जीवन की स्थिति के सुधार के आदर्शों को मानते हुए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं उन्हें इन सिद्धान्तों के आधार पर एक दूसरे से सहयोग करना चाहिये।

जब से इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है तब से निरन्तर अधिकाधिक देश इन्हें अपना रहे हैं, अथवा इन से अपनी सहमति प्रकट करते जा रहे हैं। बांडुंग सम्मेलन में एकत्रित राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से जो घोषणा की थी उनमें इन सिद्धान्तों की भी पुष्टि की गई थी। आज इन्हें राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिये एक दृढ़ नींव के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

श्री बुल्गानिन और श्री लुश्चेव की वर्तमान भारत यात्रा के दौरान में उनकी भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में खूब स्पष्ट तथा अबाध बातचीत हुई। उस वार्तालाप के फलस्वरूप उनका यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि इन पांच सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहिये तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने और राष्ट्रों में परस्पर शांति तथा सहयोग को बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अध्याय १६

टीटो-नासिर-नेहरू संयुक्त वक्तव्य

[जुलाई, १९५६]

प्रत्येक देश का परम कर्तव्य है कि वह युद्ध को दूर रखे इसलिये नहीं कि इसके पीछे कोई सैद्धांतिक कारण है, परन्तु इसलिये कि आज युग को शांति की आवश्यकता है। आज संसार में कोई महायुद्ध नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि इससे मानवता का सर्वनश हो जायेगा।

—जवाहरलाल नेहरू

[बेरुत में, २१ जुलाई, १९५६]

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, प्रेसीडेंट नासिर और प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा पूला में जारी
किये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२० जुलाई, १९५६]

तीनों राष्ट्रों की सरकारों के प्रमुखों ने, जब वे १२ महीने पहले एक दूसरे से पृथक्-पृथक् मिले थे, उस समय से लेकर अब तक की अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि पर विचार किया । अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में उनकी नीतियों की समानता के कारण उनमें घनिष्ठ सहयोग उत्पन्न हो चुका है । उन्हें यह देख कर सन्तोष हुआ कि उनके देश जिन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, उन से कुछ सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो गया है और उनसे राष्ट्रों में समता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने की भावना को बढ़ावा मिला है ।

भिन्न-भिन्न नीतियों का अनुसरण करने वाले भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के नेताओं द्वारा हाल में परस्पर बनाये रखे गये सम्पर्कों तथा परिस्थितियों एवं वातावरणों के कारण उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने तथा शांतिपूर्ण एवं सक्रिय सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों को अपनाने में बड़ी प्रेरणा मिली है । वे समझते हैं कि इस प्रकार के सम्पर्कों तथा विचार-विनिमय जारी रखना चाहिये तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

पिछले वर्ष हुए वांडुंग सम्मेलन में कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था कि जिनके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये जाने चाहियें । तीनों राजनीतिज्ञ उन दस सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि करते हैं जिनका वे सदा समर्थन करते रहे हैं ।

वे महसूस करते हैं कि आज दुनिया के संघर्षों और तनावों ने वर्तमान और भविष्य के लिये भय तथा आशंकाओं का बीज बो दिया है । जब तक संसार में यह भय तथा आशंकाएँ बनी रहेंगी तब तक विश्व में स्थायी रूप से शांति नहीं हो सकती है ।

फिर भी इन भय तथा आशंकाओं को एक दम दूर करना कठिन है और इनको धीरे-धीरे कम करने के लिये कदम उठाने होंगे । जो भी कदम तनाव को कम करने में सहायता दे सकता हो, उसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

अध्याय २०

भारत-सऊदी अरब दूसरा संयुक्त वक्तव्य

[सितम्बर, १९५६]

आज केवल सऊदी अरब ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के सभी देशों के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब देश एक दूसरे के सहयोग से, बल्कि उन लोगों के भी सहयोग से जो कि आज हमारा विरोध कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयत्न करेंगे।

—जवाहरलाल नेहरू

[२५ सितम्बर, १९५६]

रियास और नई दिल्ली में जारी किये गये सऊदी अरब के शाह इब्न सऊद और भारत के
प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२७ सितम्बर, १९५६]

बांडुंग सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पथ प्रदर्शन करने के लिये जिन सिद्धान्तों की घोषणा की है महामहिम शाह और प्रधान मंत्री उनका अनुकरण करने की घोषणा करते हैं। इनमें, मानव के मूल अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र (चार्टर) के सिद्धान्तों के प्रति समादर, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और उनकी प्रादेशिक अखण्डता की स्वीकृति, सभी जातियों को समान समझना, दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहना, और किसी भी देश की सीमाओं अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता पर आक्रमण अथवा बल प्रयोग न करना अथवा आक्रमण या बल प्रयोग करने की धमकियां न देना, ये सब बातें शामिल हैं। वे अपने दोनों देशों के बीच इन सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक प्रकार का सहयोग बढ़ाने का संकल्प करते हैं।

अध्याय २१

चीन-नेपाल संयुक्त वक्तव्य

[अक्तूबर, १९५६]

इन पांच सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि-
कोण तथा रवैये में एक खासा परिवर्तन कर
दिया है। इन्होंने केवल मित्र राष्ट्रों में ही नहीं
अपितु भिन्न-भिन्न राजनीतिक पद्धतियों का
अनुसरण करने वाले देशों में भी अन्तर्राष्ट्रीय
क्षेत्र में सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना
उत्पन्न कर दी है।

—महेन्द्र विक्रम सिंह
भारत स्थित नेपाली राजदूत
[२३ दिसम्बर, १९५४]

चीन और नेपाल के प्रधान मन्त्रियों द्वारा पीकिंग में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य का
सार-उद्धरण

[७ अक्तूबर, १९५६]

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने चीन और नेपाल के बीच परम्परागत घनिष्ठ एवं पुरानी मित्रता पर विचार किया और चीन और नेपाल के बीच राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के पश्चात् व चीन और भारत द्वारा प्रचलित शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच मौलिक पथ प्रदर्शक सिद्धान्तों—पंचशील—की प्रस्थापना के पश्चात् दोनों देशों में बढ़ती हुई मित्रता तथा पड़ोस की भावना की प्रशंसा की। दोनों पक्षों ने यह इरादा प्रकट किया कि वे इन सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने के लिये संयुक्त प्रयत्न करते रहेंगे।

दोनों प्रधान मन्त्रियों ने यह विचार व्यक्त किया कि राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व केवल आवश्यक ही नहीं, अपितु सम्भव भी है। चीन और नेपाल की सरकारें इन पांच सिद्धान्तों के अनुसार एशिया और अफ्रीका में तथा विश्व भर में शांति को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयत्नशील रहेंगी और एशिया तथा अफ्रीका के देशों में सहयोग तथा संगठन की भावना बढ़ाने के लिये प्रयत्न करती रहेंगी। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि अधिकाधिक देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन पांच सिद्धान्तों का समर्थन कर रहे हैं तथा इनको स्वीकार कर रहे हैं।

अध्याय २२

भारत-इथोपिया संयुक्त वक्तव्य

[नवम्बर, १९५६]

मेरे देश की विदेश नीति के भी यही आधार भूत सिद्धान्त हैं। एशियाई-अफ्रीकी दोनों के बांडुंग सम्मेलन में इथोपिया पहले ही पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार कर चुका है। वास्तव में इसाई धर्म के भी यही मूल-भूत सिद्धान्त हैं।

—हेल सेलासी

[२८ अक्तूबर, १९५६]

इथोपिया के सम्राट महामहिम हेल सेजासी प्रथम और प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा दिल्ली
में जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[८ नवम्बर, १९५६]

महामहिम सम्राट तथा भारत के प्रधान मन्त्री ने सम्राट की भारत यात्रा के समय पारस्परिक हित की बातों पर अनौपचारिक तथा मित्रतापूर्वक विचार-विनिमय किया। उन्होंने मानव प्रतिष्ठा तथा स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाली और व्यक्तियों को शस्त्रों के बल पर दास बनाने वाली गम्भीर तथा भयावह स्थिति के बारे में चिन्ता प्रकट की। उन्होंने आशा प्रकट की कि जो लोग इस स्थिति में ग्रस्त हैं वे अब भी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों का आदर करेंगे और वे संयुक्त राष्ट्र के युद्ध की आशंका को समाप्त करने, आक्रमण को रोकने तथा अशांत क्षेत्रों में शांति की स्थापना करने के प्रयत्नों में उसकी सहायता करेंगे तथा उसके साथ सहयोग करेंगे।

महामहिम सम्राट तथा भारत के प्रधान मन्त्री का दृढ़ विश्वास है कि उनके देशवासियों को विकास, सामाजिक प्रगति तथा जीवन के स्तर को ऊँचा बनाने का अवसर देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का कम होना तथा विश्व शांति का बना रहना बड़ा आवश्यक है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि पंच-शील के इन सिद्धान्तों के—एक दूसरे की प्रभु-सत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता का समादर, अनाक्रमण, दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग तथा समता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व—अनुपालन से ही अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो सकता है और संसार के देशों में परस्पर समबोध तथा सहयोग बढ़ सकता है।

महामहिम सम्राट और प्रधान मन्त्री ने एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन द्वारा बांडुंग में घोषित उपनिवेशवाद, जातिवाद और उस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग और प्राविधिक सहायता के आदान-प्रदान के बारे में जो सिद्धान्त घोषित किये थे, उनकी पुष्टि की।

अध्याय २३

भारत-सीरिया संयुक्त वक्तव्य

[जनवरी, १९५७]

हम किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के गुण-दोषों को उन पांच सिद्धांतों (पंचशील) के आधार पर देखते हैं, जिनके लिये आज भारत विश्व भर में विख्यात हो गया है और जिन्हें मानव इतिहास में बांडुंग सम्मेलन के संकल्पों में युग प्रवर्तनकारी सिद्धान्तों के रूप में मूर्त रूप दिया गया है—तथा उन सम्बन्धों तथा सिद्धान्तों के आधार पर जिन्होंने हमारी किसी भी गुट में न शामिल होने की सक्रिय तटस्थता की जो कि अकेले रहने की नीति कदापि नहीं है, नीति को जन्म दिया है। हम किसी भी मामले में अलग नहीं रहना चाहते हैं किन्तु साथ ही हम किसी भी गुट में नहीं मिलना चाहते हैं। हम इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में अपना खूँया निर्धारित करते हैं।

—शुक्ररी अल क्वातली

[१७ जनवरी, १९५७]

सीरिया के प्रेजीडेंट क्वातली और प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा नई दिल्ली में जारी किये गये

संयुक्त वक्तव्य का सार-उद्धरण

[२१ जनवरी, १९५७]

दोनों राजनीतिज्ञों का यह मत था कि एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त वर्तमान काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के साथ विश्व में एक नई चेतना प्रारम्भ हो गई है। इस चेतना को एशिया तथा अफ्रीका के देशों के अप्रैल, १९५५ में हुए बांडुंग सम्मेलन में मूर्त स्वरूप प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं ने सीरिया तथा भारत की सभी राष्ट्रों से मित्रता तथा शांति की इच्छा तथा बांडुंग सम्मेलन के सिद्धान्तों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्थापित करने की इच्छा की पुष्टि की। उन्होंने सभी राष्ट्रों को उन सिद्धान्तों को खास कर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अनाक्रमण तथा अहस्तक्षेप के सिद्धान्त को अपनाने की अपील की। उन्होंने यह कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बांडुंग घोषणा की विचारधारा के लाने के लिये उसके अनुकूल स्थितियाँ पैदा करनी होंगी। दोनों देशों द्वारा अपनायी जा रही किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति से संसार में शांति तथा सहयोग की भावना को बड़ा योग मिल सकता है और इससे बांडुंग सम्मेलन के सिद्धान्तों को भी सफलता मिल सकती है।

अध्याय २४

भारत-पोलैंड दूसरा संयुक्त वक्तव्य

[मार्च, १९५७]

मैं दूसरों के बौद्धिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक सभी प्रकार के विचारों को सुनने के लिये तैयार हूँ। मैं हरदम दूसरों के अनुभवों से सीखने को तैयार हूँ। किन्तु मैं अपनी करनी को अपने हाथ में रखूंगा। प्रत्येक देश को एक दूसरे की इस भावना को सहानुभूति तथा मैत्रीपूर्ण समवबोध के साथ देखना चाहिये और उसमें किसी प्रकार का दखल अथवा दबाव नहीं डालना चाहिये।

—जवाहरलाल नेहरू

[१७ सितम्बर, १९५५]

भारत तथा पोलैंड के प्रधान मन्त्रियों द्वारा नई दिल्ली में दिये गये संयुक्त वक्तव्य का
सार-उद्धरण

[२७ मार्च, १९५७]

पोलैंड सरकार के शिष्टमंडल की ओर से श्री सिरेंकीविज ने श्री नेहरू से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा अन्य मामलों में बातचीत की। प्रधान मन्त्रियों ने जून १९५५ में वासा में दोनों देशों द्वारा आपसी सम्बन्ध तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये स्वीकृत सिद्धान्तों की पुनः पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वतन्त्र तथा सर्व प्रभुत्व सम्पन्न देशों को इन्हीं सिद्धान्तों के, जिनको कि आज एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रों में सहयोग बढ़ाने वाले सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, आधार पर अपने सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें।

आज की हलचलों से भरी हुई दुनिया में हम इन सिद्धान्तों को फिर दोहराते हैं। वे सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

- (१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता के प्रति परस्पर समादर;
- (२) अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में किसी भी कारण से आर्थिक, राजनीतिक अथवा सैद्धांतिक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना;
- (४) समता तथा परस्पर सहयोग; और
- (५) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

वे विश्वास करते हैं कि भिन्न-भिन्न देशों द्वारा इन सिद्धान्तों पर अमल किये जाने से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक समस्याओं को हल किया जा सकता है।

अध्याय २५

भारत-चिली संयुक्त वक्तव्य

[अप्रैल, १९५७]

नये वक्तव्य में 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के सिद्धान्त को न रख कर पुराने पंचशील के सिद्धान्तों से एक महत्वपूर्ण अन्तर किया गया है। इसके स्थान पर संयुक्त वक्तव्य में यह कहा गया है कि "अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिमय ढंग से हल किया जाये"।

—प्रेस टिप्पणी

हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड

[१७ अप्रैल, १९५७]



चिली के विदेश मन्त्री तथा भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य
का-सार-उद्धरण

[१६ अप्रैल, १९५७]

चिली के विदेश कार्य मन्त्री और भारत के प्रधान मन्त्री विशेष रूप से इस बात में अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि उनके दोनों देश निम्नलिखित सामान्य बातों पर सहमत हैं :

- (१) राष्ट्रों की समता तथा उनकी प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभु-सत्ता का समादर;
- (२) दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
- (३) आक्रमण को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों का साधन न बनाना;
- (४) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की आवश्यकता और उसका लाभप्रद होना;
- (५) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना ।

अध्याय २६

भारत-लंका संयुक्त-वक्तव्य

[मई, १९५७]

विश्व को युद्ध और पूर्ण सर्वनाश और
शांति व पंचशील के बीच चुनाव करना है ।
इसके अतिरिक्त और कोई तीसरा मार्ग नहीं है ।

—जवाहरलाल नेहरू

[१६ अगस्त, १९५६]

पुस्तकालय

भारत और लंका के प्रधान मन्त्रियों द्वारा कोलम्बो में दिये गये संयुक्त वक्तव्य का
सार-उद्धरण

[१६ मई, १९५७]

दोनों प्रधान मन्त्री पंचशील के नाम से सर्व विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के पांच सिद्धान्तों में, जिनको कि बांडुंग सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सिद्धान्तों में सम्मिलित तथा विस्तृत रूप में व्यक्त किया गया है, अपना विश्वास प्रकट करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि अगर इन सिद्धान्तों पर अमल किया जाये तो इन से ऐसे देशों में भी परस्पर मैत्री, समवबोध तथा सहयोग बढ़ सकता है, जिनका परस्पर कुछ सैद्धांतिक तथा अन्य प्रकार का मतभेद है। इस से विश्व में तनाव भी कम हो जायगा और साथ ही आजकी दुनिया के सामने जो विकट संघर्ष चल रहे हैं, वे भी टाले जा सकेंगे।

ARCHIVES DATA BASE
2011 - 12

R 9.5, PAN-P



38073

५६

M61LS-500-17-12-57-GIPF

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

SAMPLE STOCK

1988
VERIFIED BY

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

RR(H) No. 4

लोक-सभा सचिवालय, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित

नवम्बर, १९५७

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद में मुद्रित